पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

सीता पांडे

बनाम

बिहार राज्य एवं अन्य

2023 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं.5407

23 अगस्त, 2023

(माननीय मुख्य न्यायाधीश और माननीय न्यायमूर्ति श्री पार्थ सारथी)

विचार के लिए मुद्दा

क्या अपील खारिज होने के अगले ही दिन करदाता के बैंक खातों से जबरन और गुप्त रूप से की गई वसूली सही है या नहीं?

हेडनोट्स

बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017-धारा 78, 108, 109, 112(8)-वसूली-करदाता विभिन्न प्रतिष्ठानों को सुरक्षा और सफाई सेवाओं सहित जनशक्ति आपूर्ति का व्यवसाय करता है; जिसमें सरकारी पॉलिटेक्निक संस्थान शामिल हैं- वैधानिक प्रावधानों और जारी अधिसूचनाओं की अनदेखी करते हुए, वसूली मनमाने ढंग से और बिना किसी नोटिस के की गई थी- इस प्रकार, याचिकाकर्ता करदाता के अपीलीय उपाय को विफल कर दिया गया और करदाता के व्यवसाय को खतरे में डाल दिया गया- कोई अपीलीय न्यायाधिकरण गठित नहीं किया गया था और केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों द्वारा अधिसूचनाएं जारी की गई थीं, जो ऐसे न्यायाधिकरणों के गठन की तारीख से ही शुरू होने वाली सीमा की अवधि का प्रावधान और विस्तार करती थीं।

निर्णय: दिशानिर्देश: (1) अपील दायर करने के लिए समय सीमा के भीतर कर की वसूली नहीं की जाएगी और जब उचित रूप से संस्थित अपील में स्थगन आवेदन दायर किया जाता है, तो अपीलीय प्राधिकारी द्वारा स्थगन आवेदन का निपटारा किए जाने से पहले; (2) यहां तक कि जब अपील में स्थगन आवेदन का निपटारा कर दिया जाता है, वसूली केवल उचित अवधि के बाद शुरू की जाएगी ताकि करदाता उच्च फोरम में जा सके; (3) हालांकि, ऐसे मामलों में जहां मूल्यांकन अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि करदाता मांग को नकार सकता है या यह राजस्व के हित में समीचीन है, जैसा कि धारा 78 के प्रावधान के तहत प्रदान किया गया है, करदाता को नोटिस के साथ वसूली हो सकती है, जो नोटिस इसे शुरू करने के कारणों को दर्शाता है और कम समय को निर्दिष्ट करता है जिसके भीतर करदाता को बकाया राशि को पूरा करने का निर्देश दिया जाता है; (4) हालांकि बैंक खाता संलग्न किया जा सकता है; राशि निकालने से पहले, करदाता को उचित पूर्व सूचना दी जानी चाहिए ताकि करदाता अपना अभ्यावेदन दे सके या कानून में उपाय का सहारा ले सके - कर अधिनियम के तहत प्राधिकारी केवल कर संग्रहकर्ता के रूप में कार्य नहीं करेंगे, बल्कि एक अर्ध-न्यायिक प्राधिकारी के रूप में कार्य करेंगे, जिसे राजस्व के हितों की रक्षा करने का सार्वजनिक कर्तव्य सौंपा गया है, साथ ही करदाता की कठिनाई को कम करने की आवश्यकता को संतुलित करना होगा - धारा 112 में अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष द्वितीय अपील के लिए प्रथम अपीलीय चरण में भुगतान की गई दस प्रतिशत राशि के अतिरिक्त देय कर राशि का बीस प्रतिशत देने का प्रावधान है—धारा 112(8) के अंतर्गत ऐसा भुगतान किए जाने पर, आगे की वसूली कार्यवाही स्थगित रखने की भी

आवश्यकता है—जब्ती की गई कुल राशि में से शेष राशि आज से दो सप्ताह के भीतर करदाता को चुकाई जानी चाहिए, अन्यथा ब्याज 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से लगेगा—आदेश जारी करने वाले अधिकारी, जिसने वैधानिक प्रावधानों और स्थापित कानूनी सिद्धांतों का पूर्णतः उल्लंघन करते हुए कार्य किया है, को करदाता को लागत के रूप में 5,000/- (पाँच हज़ार) रुपये का भुगतान करना होगा—रिट याचिका निर्देशों और दिशानिर्देशों के साथ स्वीकृत।

(पैराग्राफ 14 से 16, 19 से 22)

न्याय दृष्टान्त

मोहिंदर सिंह गिल एवं अन्य बनाम मुख्य चुनाव आयुक्त, नई दिल्ली एवं अन्य, एआईआर **1978** एससी **851;** यूटीआई म्यूचुअल फंड बनाम आयकर अधिकारी एवं अन्य, **(2012) 345** आईटीआर **71** (बॉम्बे**)—भरोसा किया गया।**

अधिनियमों की सूची

बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017

मुख्य शब्दों की सूची

कर,वसूली, करदाता, अर्ध-न्यायिक प्राधिकारी, अपीलीय प्राधिकारी, नोटिस, अधिसूचना।

प्रकरण से उत्पन्न

अपील की अस्वीकृति के अगले ही दिन करदाता के बैंक खातों से अनाधिकृत एवं गुप्त रूप से की गई वसूली से।

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

याचिकाकर्ताओं के लिए: श्री साकेत तिवारी,अधिवक्ता; श्री राकेश कुमार सिंह,अधिवक्ता; श्री अमृत्य राज, अधिवक्ता।

उत्तरदाताओं के लिएः श्री विवेक प्रसाद **(जीपी-7)**

रिपोर्टर द्वारा हेडनोट बनाया गया: आभाष चंद्र

माननीय पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2023 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं.5407

==========

सीता पांडे, एक वयस्क महिला, आयु लगभग 53 वर्ष, पति विश्वनाथ पांडे, निवासी-गाँव-कुरथौल, थाना-परसा बाजार जिला-पटना(बिहार)। स्वामी- ओम श्री सुरक्षा सेवा कार्यालय पता-कुरथौल, थाना-परसा बाजार, जिला-पटना।

... ... याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. राज्य कर आयुक्त, पटना के माध्यम से बिहार राज्य।
2. राज्य कर (अपील) के संयुक्त आयुक्त, पटना उत्तर सर्कल, पटना।
3. सहायक राज्य कर आयुक्त, पटना उत्तर सर्कल, पटना।
4. सहायक राज्य कर आयुक्त, पटना उत्तर सर्कल, पटना।

... ... उत्तरदाता/ओं

==========

उपस्थिति :

याचिकाकर्ता/ओं के लिए: श्री साकेत तिवारी, अधिवक्ता

श्री राकेश कुमार सिंह, अधिवक्ता

श्री अमृत राज, अधिवक्ता

उत्तरदाता/ओं के लिए: श्री विवेक प्रसाद (जीपी-7)

==========

कोरमः माननीय मुख्य न्यायाधीश

एवं

माननीय न्यायमूर्ति श्री पार्थ सारथी

मौखिक निर्णय

(प्रतिः माननीय मुख्य न्यायाधीश)

दिनांक: 23-08-2023

1. *"न्यायिक शक्तियों से संपन्न साहसी कर अधिकारियों में अपनी पूर्व भूमिका को न्यायिक भूमिका की तुलना में अधिक याद रखने की प्रवृत्ति होती है। एक कल्याणकारी राज्य में और न्यायिक*

प्रक्रिया की प्रकृति को समझते हुए, विभिन्न कारणों से प्रेरित इस तरह के रवैये की सराहना नहीं की जा सकती। इन मानदंडों से विचलन का दंड पारित आदेश के लिए खतरा है। प्रशासनिक शक्ति के प्रयोग पर दुर्भावना का प्रभाव सुस्थापित है।"

[आर.एस. जोशी, बिक्री कर अधिकारी, गुजरात और अन्य बनाम अजीत मिल्स लिमिटेड औरअन्य; (1977) 4 एससीसी 98]

2. यह एक कर कार्यपालक द्वारा एक वीरतापूर्ण अतिक्रमण का एक उत्कृष्ट मामला है; अपील खारिज होने के ठीक एक दिन बाद देय कर की वसूली; जब एक और अपील प्रदान की गई थी और जिस न्यायाधिकरण के समक्ष ऐसी अपील दायर की जानी है, उसका गठन नहीं किया गया था।

3. तथ्यों पर, यह ध्यान देने के लिए पर्याप्त है कि निर्धारिती विभिन्न प्रतिष्ठानों को सुरक्षा और सफाई सेवाओं सहित मानव शक्ति की आपूर्ति का व्यवसाय करता है; जिसमें सरकारी पॉलिटेक्निक संस्थान शामिल हैं। यह मुद्दा उठा कि क्या सरकारी पॉलिटेक्निक संस्थानों को प्रदान की जाने वाली सेवाएं अधिसूचना संख्या 12/2017 दिनांक 28.06.2017 की प्रविष्टि संख्या 66 (ख) (iii) में निर्धारित छूट के तहत आती हैं, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि यह उच्च माध्यमिक विद्यालय या समकक्ष तक के शैक्षणिक संस्थानों द्वारा या उन्हें प्रदान की जाने वाली सेवाएं हैं। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा जारी ज्ञापन में भी भरोसा किया गया था, जिसमें पॉलिटेक्निक को इंटरमीडिएट यानी उच्च माध्यमिक के समकक्ष माना गया था।

4. हम छूट के रूप में उठाए गए कानूनी मुद्दे पर ध्यान नहीं देंगे क्योंकि निर्धारिती के पास एक अपीलीय उपाय है जो समाप्त नहीं हुआ है और जिस मंच पर ऐसी अपील की जानी है, उसका गठन अभी तक नहीं किया गया है। हम केवल अपील की अस्वीकृति के अगले ही दिन निर्धारिती के बैंक खातों से आकस्मिक और गुप्त रूप से की गई वसूली से संबंधित हैं।

5. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री साकेत तिवारी का कहना है कि वसूली सबसे मनमाने तरीके से की गई थी, विशेष रूप से जब कोई अपीलीय न्यायाधिकरण गठित नहीं किया गया था और केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों द्वारा अधिसूचनाएं जारी की गई थीं, जिसमें ऐसे न्यायाधिकरणों के गठन की तारीख से ही सीमा की अवधि का प्रावधान और विस्तार किया गया था। यह भी बताया गया है कि इस तरह के मामलों में यह न्यायालय लगातार 20 प्रतिशत के भुगतान का निर्देश दे रहा है, जैसा कि बिहार वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा

112 (8) में प्रावधान किया गया है (जिसे इसके बाद "बी. जी. एस. टी. अधिनियम" के रूप में संदर्भित किया गया है) और तब तक वसूली पर रोक लगा रहा है जब तक कि न्यायाधिकरण का गठन नहीं हो जाता और उस तारीख से तीन महीने की सीमा पार नहीं हो जाती। वर्तमान मामले में, वैधानिक प्रावधानों और जारी अधिसूचनाओं की अनदेखी करते हुए, वसूली मनमाने ढंग से और बिना किसी सूचना के की गई थी। इस प्रकार, याचिकाकर्ता करदाता के अपीलीय उपाय को निष्फल कर दिया गया है और करदाता के व्यवसाय को ही संकट में डाल दिया गया है। याचिकाकर्ता ने वसूल की गई राशि की वापसी और अपील में पुष्टि किए गए कर निर्धारण आदेश पर तब तक रोक लगाने का अनुरोध किया है जब तक कि बी. जी. एस. टी अधिनियम की धारा 109 के तहत अपीलीय न्यायाधिकरण का गठन नहीं हो जाता। विद्वान अधिवक्ता श्री साकेत तिवारी ने कर प्राधिकरण के अत्याचारपूर्ण कृत्य से याचिकाकर्ता के व्यवसाय को हुए नुकसान के लिए वसूली गई राशि पर ब्याज और असाधारण लागत की भी मांग की है।

6. दूसरी ओर, विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री विवेक प्रसाद, बी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 78 और इसके प्रावधान पर भरोसा करते हैं जो तीन महीने की अवधि के भीतर भी वसूली को सक्षम बनाता है, यदि उचित अधिकारी इसे राजस्व के हित में समीचीन समझता है। वर्तमान मामले में, वसूली अधिकारी द्वारा लिखित रूप में कारण दर्ज किए गए हैं और इसलिए, वसूली को कानून की रूपरेखा के भीतर अच्छी तरह से किया गया है। कर देयता के 20 प्रतिशत के भुगतान पर वसूली पर रोक लगाने के संबंध में निर्णय बाद में वर्तमान मामले में वसूली के लिए आया। वसूली में कोई दुर्भावना नहीं है और यह केवल वित्तीय वर्ष के समापन के कारण उत्पन्न होने वाली सुविधा को ध्यान में रखते हुए किया गया था। विद्वान सरकारी अधिवक्ता रिट याचिका को खारिज करने की मांग करेंगे।

7. निर्धारिती को अनुलग्नक-2 के रूप में प्रस्तुत एक मूल्यांकन आदेश दिनांक 14.12.2022 को जारी किया गया था। बी. जी. एस. टी. और सी. जी. एस. टी. अधिनियम के तहत राशि प्रत्येक रूप में 18,91,609.00 रुपये थी। दोनों अधिनियमों के तहत रु. 16,02,552.00 की ब्याज राशि और रु. 1,89,161.00 का जुर्माना भी देय था।कुल देनदारी 73,66,644.00 रु जिसे अनुलग्नक-2 के अनुसार 14.03.2023 पर या उससे पहले भुगतान करने का निर्देश दिया गया था। निर्धारिती ने एक अपील दायर की जिसका अपीलीय प्राधिकरण ने समर्थन नहीं किया, जिसने इसे 27.03.2023 पर खारिज कर दिया, जैसा कि अनुलग्नक-1 से स्पष्ट है। अगले दिन तुरंत, निर्धारण अधिकारी ने उन चार बैंकों के शाखा प्रबंधकों को

अनुलग्नक-3 नोटिस जारी किया, जिनमें निर्धारिती खाते रखता था। कुल राशि 69,88,322.00 रु की वसूली की मांग की गई थी जिसमें सी. जी. एस. टी. और एस. जी. एस. टी. अधिनियमों के तहत समान देनदारियां शामिल थीं। प्रत्येक अधिनियम के तहत जमा की गई 10 प्रतिशत राशि, जो अपीलीय स्तर पर 1,89,161.00 रुपये थी, वसूली नोटिस जारी होने पर कटौती की गईथी। अनुलग्नक-3 में वसूली सूचना दिनांकित है और पूरी राशि बरामद कर ली गई है जिसके परिणामस्वरूप इस न्यायालय के समक्ष वर्तमान चुनौती दी गई है।

8. सी. जी. एस. टी. अधिनियम में अपीलीय प्राधिकरण या पुनरीक्षण प्राधिकरण द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई के लिएअपीलीय न्यायाधिकरण के गठन का प्रावधान है और बी.जी.एस.टी. अधिनियम की धारा 109 में सी.जी.एस.टी. अधिनियम के अंतर्गत गठित उक्त अपीलीय न्यायाधिकरण को बी.जी.एस.टी. अधिनियम के अंतर्गत अपीलों की सुनवाई का भी प्रावधान है। धारा 112 किसी भी व्यक्ति को, जो बी.जी.एस.टी अधिनियम या सी.जी.एस.टी. अधिनियम की धारा 107 या धारा 108 के अंतर्गत उसके विरुद्ध पारित किसी आदेश से व्यथित है, ऐसे आदेश के विरुद्ध अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील करने का अधिकार देती है, जिस तारीख से अपील किए जाने वाले आदेश की अपील करने वाले व्यक्ति को सूचना दी जाती है। धारा 112 की उप-धारा (8) अपील के लिए संस्थित होना अनिवार्य बनाती है; अपीलकर्ता, आक्षेपित आदेश से उत्पन्न कर, ब्याज, जुर्माना, शुल्क और दंड की पूरी राशि का भुगतान करता है जैसा कि उसने स्वीकार किया है और धारा 107(6) के तहत भुगतान की गई राशि के अतिरिक्त, विवादित कर की शेष राशि के बीस प्रतिशत के बराबर राशि का भुगतान करता है। इसलिए, धारा 107 (6) के तहत भुगतान किए गए दस प्रतिशत के अलावा, कर और अन्य बकाया की स्वीकृत राशि को विवादग्रस्त कर के बीस प्रतिशत के साथ पूरा करना होगा।इस तरह का भुगतान किए जाने पर, न केवल स्थापित अपील बनाए रखने योग्य है; धारा 112 की उप-धारा (9) के तहत, अपील के निपटारे तक शेष राशि के लिए वसूली कार्यवाही पर एक मानित रोक है। इसलिए, जब अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष एक उचित अपील दायर की जाती है, जिसमें अपील को बनाए रखने के लिए आवश्यक भुगतान शामिल होते हैं, तो मूल्यांकन आदेश या प्रथम अपीलीय आदेश के आधार पर कोई भी वसूली करने पर वैधानिक प्रतिबंध होता है।

9. इसी संदर्भ में धारा 78 के परंतुक पर विचार किया जाना चाहिए। धारा 78 में नाममात्र का शीर्षक "वसूली कार्यवाही की शुरुआत" है और एक कर योग्य व्यक्ति से ऐसे आदेश की सेवा की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर देय राशि का भुगतान करके बी. जी.

एस. टी. अधिनियम के तहत पारित आदेश को पूरा करने की आवश्यकता होती है। परंतुक उचित अधिकारी को समीचीन परिस्थितियों में, राजस्व के हित में, लिखित रूप में दर्ज कारणों के लिए, कर योग्य व्यक्ति से तीन महीने की अवधि से कम की अवधि के भीतर ऐसा भुगतान करने की अपेक्षा करने में सक्षम बनाता है, जो उसके द्वारा निर्दिष्ट किया जाए।वर्तमान मामले में, यह स्वीकार किया जाता है कि तीन महीने के भीतर समय निर्दिष्ट करने वाला कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है, जिसके भीतर निर्धारिती को आदेश के अनुसार राशि का भुगतान करना था।

10. विद्वान सरकारी अधिवक्ता का तर्क यह भी है कि नोटिस की कोई आवश्यकता नहीं है और केवल कारणों को दर्ज किया जाना है, जो फाइलों में उपलब्ध है, जिसका एक उद्धरण उत्तरदाता संख्या 2 और 3 की ओर से दायर पूरक जवाबी हलफनामे दिनांक 10.05.2023 के साथ अनुलग्नक-घ के रूप में प्रस्तुत किया गया है। फ़ाइल के अंश से स्पष्ट है कि दिनांक 27.03.2023 को दर्ज कारण यह है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 समाप्त होने जा रहा है और उसके तुरंत बाद लगातार बैंक अवकाश हैं।" हम अधिकारी द्वारा दर्ज किए गए कारणों में अपनी गहरी पीड़ा और असंतोष व्यक्त किए बिना नहीं रह सकते। हमें डर है कि 2 या 3 दिनों की आसन्न बैंक छुट्टियों और वित्तीय वर्ष के समापन को धारा 78 के प्रावधान के तहत शीघ्र वसूली को सही ठहराने के लिए वैध कारण नहीं कहा जा सकता है और यह स्पष्ट नहीं है कि राजस्व का ब्याज कैसे प्रभावित होगा, यदि वसूली को तीन महीने के लिए स्थगित रखा जाता है या कम से कम निर्धारिती को बैंक से वसूली करने से पहले एक नोटिस जारी किया जाता है। जवाबी हलफनामे में वसूली से पहले निर्धारिती को कोई नोटिस दिए जाने की बात नहीं की गई है। निर्धारिती के बैंकों को नोटिस जारी किए गए और विभिन्न खातों में शेष राशि को जबरन जब्त कर, कर विभाग को भुगतान कर दिया गया।

11. जहाँ तक वैधानिक प्रावधान है जिसमें निर्धारिती को नोटिस की आवश्यकता नहीं है, हमें ***केवल मोहिंदर सिंह गिल और एक अन्य बनाम मुख्य चुनाव आयुक्त, नई दिल्ली और अन्य; ए. आई. आर. 1978 सुप्रीम कोर्ट 851*** मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के संविधान पीठ के फैसले का उल्लेख करने की आवश्यकता है जिससे हम नीचे कंडिका 75 और 76 उद्धृत करते हैं:-

> *"75. इस प्रकार निष्पक्ष सुनवाई चुनाव को रद्द करने का निर्णय लेने का एक अभिधारणा है, हालांकि उस प्रक्रिया को निष्पक्ष रूप से संक्षिप्त करने की अनुमति है।यह साक्ष्य के नियमों*

या परीक्षण के रूपों के बिना निष्पक्ष हो सकता है। यदि प्रभावितों को अवगत कराना और अभ्यावेदन का मूल्यांकन करना अनुपस्थित है तो यह उचित नहीं हो सकता है। प्राकृतिक न्याय के पीछे का दर्शन, एक मायने में, कानून के लोकतांत्रिक शासन की प्रक्रिया में सहभागी न्याय है।

76. हमें बताया गया है कि जहां भी संसद सुनवाई का इरादा रखती है, उसने अधिनियम और नियमों में ऐसा कहा है और अनुमानित रूप से जहां उसने निर्दिष्ट नहीं किया है, वह अनुचित है।ऐसा कोई क्रम नहीं है। कानून के मौन का कोई बहिष्करण प्रभाव नहीं होता है सिवाय इसके कि यह आवश्यक निहितार्थ से प्रवाहित होता है। अनुच्छेद 324 एक व्यापक शक्ति निहित करता है और जहां उम्मीदवारों पर इसके प्रयोग से कुछ प्रत्यक्ष परिणाम निकलते हैं, हमें इस कार्यात्मक दायित्व को पढ़ना चाहिए।"

[हम जोर देने के लिए रेखांकित करते हैं]

12. चुनाव को रद्द करने के निर्णय के संबंध में की गई कानून की उपरोक्त घोषणा, प्रत्येक न्यायिक और अर्ध-न्यायिक आदेश और की गई कार्रवाई पर लागू होती है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत एक सांविधिक प्राधिकारी द्वारा की गई प्रत्येक दंडात्मक कार्रवाई में अंतर्निहित हैं, यहां तक कि कानून के चारों कोनों के भीतर भी; जब यह सामान्य परिस्थितियों में उस व्यक्ति के लिए पूर्वाग्रह पैदा कर सकता है जिसके विरूद्ध ऐसी कार्यवाही की जाती है। धारा 78 के प्रावधान में सामने आने वाले कारणों की रिकॉर्डिंग को गुप्त रूप से दर्ज नहीं किया जाना चाहिए और फाइलों में रखा जाता है, लेकिन निर्धारिती को सूचित किया जाता है और भुगतान करने के लिए तीन महीने के भीतर एक समय निर्दिष्ट किया जाता है। वास्तव में, परंतुक को पढ़ने पर हमारी निश्चित राय है कि नोटिस की आवश्यकता है, यदि कारणों को दर्ज करने से पहले नहीं; कम से कम उन कारणों की सूचना जो उचित अधिकारी को देय राशि की वसूली के लिए प्रेरित करते हैं, इस तरह की वसूली को अवधि के स्पष्ट विनिर्देश के साथ राजस्व के हित में समीचीन मानते हुए; तीन महीने की अवधि से कम, जिसके भीतर राशियों का भुगतान किया जाना है।

13. धारा 78 में प्रावधान है कि एक व्यक्ति जिसके विरूद्ध आदेश पारित किया जाता है, वहतीन महीने की अवधि के भीतर देय राशियों को पूरा करेगा और परंतुक निर्धारण अधिकारी

को तीन महीने से कम अवधि के दौरान भी ऐसे बकाया की संतुष्टि प्राप्त करने का अधिकार देता है। प्रावधान इस प्रकार लिखा गया हैः-

> *"**78. वसूली कार्यवाही का आरम्भ** - इस अधिनियम के तहत पारित आदेश के अनुसरण में एक कर योग्य व्यक्ति द्वारा देय कोई भी राशि ऐसे व्यक्ति द्वारा ऐसे आदेश की सेवा की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर भुगतान की जाएगी, जिसमें विफल रहने पर वसूली की कार्यवाही शुरू की जाएगीः*
>
> *बशर्ते कि जहां उचित अधिकारी राजस्व के हित में इसे समीचीन समझता है, वह लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए उक्त कर योग्य व्यक्ति से <u>तीन महीने की अवधि से कम अवधि के भीतर ऐसा भुगतान करने की अपेक्षा कर सकता है जो उसके द्वारा निर्दिष्ट किया जाए</u>।*
>
> *[<u>जोर देने के लिए हमारे द्वारा रेखांकित</u>]*

इसलिए, जब कारणों को लिखित रूप में दर्ज किया जाता है, तो निर्धारण अधिकारी पर यह कर्तव्य होता है कि वह उस समय को निर्दिष्ट करे जिसके भीतर राशियों का भुगतान किया जाना है, जिसकी सूचना निर्धारिती को देनी होती है।

14. इस संदर्भ में, हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि सी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 109 के तहत अपीलीय न्यायाधिकरण का गठन अभी तक नहीं किया गया है।हम धारा 112 (8) के तहत देय शेष कर के बीस प्रतिशत के भुगतान पर वसूली पर रोक लगाने वाली विभिन्न याचिकाओं में इस न्यायालय द्वारा जारी न्यायसंगत निर्देशों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करेंगे। हालाँकि, यह बहुत स्पष्ट है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार भी इस तथ्य से अवगत थी कि न्यायाधिकरण का गठन अभी तक नहीं किया गया था। दो अधिसूचनाएँ, एक केंद्र सरकार की और दूसरी राज्य सरकार की, रिट याचिका के साथ अनुलग्नक 8 और 9 के रूप में प्रस्तुत की जाती हैं।ये दोनों अधिसूचनाएँ सी. जी. एस. टी. और बी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 172 के तहत क्रमशः प्रदत्त शक्तियों का आह्वान करती हैं। कठिनाइयों को दूर करने के लिए, संभवतः न्यायाधिकरण के गैर-गठन के कारण, दोनों अधिनियमों की धारा 112 की उप-धारा (1) के तहत निर्धारित तीन महीने की सीमा अवधि को निम्नलिखित तिथियों में से बाद की तारीख तक बढ़ा दिया गया है; (i) आदेश के संचार का या (ii) वह तारीख जिस पर राष्ट्रपति या राज्य अध्यक्ष,

जैसा भी मामला हो, धारा 109 के तहत इसके गठन के बाद अपीलीय न्यायाधिकरण के कार्यालय में प्रवेश करता है। यह भी निर्धारित किया गया है कि धारा 112 (3) के तहत प्रदान की गई छह महीने की अवधि भी उपरोक्त तिथियों से उसी अवधि तक बढ़ाई जाएगी; जो भी तारीख बाद में आती है। इसलिए, बैंकों को नोटिस जारी करके और उन्हें राशि का भुगतान करने के लिए मजबूर करके, वह भी कर, ब्याज और जुर्माने सहित पूरी देय राशि, गुप्त रूप से वसूली नहीं हो सकती थी।

15. विधानमंडल ने, न्यायाधिकरण में दायर एक अपील की स्थिति में, केवल कर बकाया का बीस प्रतिशत भुगतान करने का इरादा किया था; जिस पर भुगतान अपील के निपटान तक पूरी मांग पर रोक लगाने के लिए उत्तरदायी था।हालांकि, स्वीकृत कर; ब्याज, जुर्माना और जुर्माना भी संतुष्ट होना चाहिए।इसलिए भले ही दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती थी, कर अधिकारी को इसे पहले अपीलीय चरण में भुगतान किए गए दस प्रतिशत और किसी भी स्वीकृत कर के अलावा, यदि भुगतान नहीं किया गया हो, तो कुल निर्धारित राशि के बीस प्रतिशत तक सीमित रखना चाहिए था। कर अधिकारी ने निश्चित रूप से गलती की थी, वह भी बहुत गंभीर रूप से, इस हद तक कि उनकी कार्रवाई को अतिशयोक्तिपूर्ण करार दिया गया था, गुप्त रूप से कर, ब्याज और जुर्माने के रूप में पूरी राशि की वसूली करने में, यहां तक कि विधायी जनादेश के विपरीत जैसा कि हमने पाया, बताए गए कारण अविश्वसनीय और स्पष्ट रूप से अस्थिर हैं और वित्तीय वर्ष के अंत का निकट आना केवल उच्च अधिकारियों द्वारा सौंपे गए व्यक्तिगत लक्ष्यों को बढ़ाने के लिए एक प्रेरणा हो सकती है।

16. ***यू. टी. आई. म्यूचुअल निधि बनाम आयकर अधिकारी और अन्य; [2012] 345 आईटीआर 71(बोम), में*** निर्धारित उक्ति का पालन करते हुए जहाँ तक वसूली का संबंध है, हम निम्नलिखित दिशानिर्देश जारी करते हैंः-

(1). अपील दायर करने के लिए समय सीमा के भीतर कर की कोई वसूली नहीं होगी और जब अपीलीय प्राधिकरण द्वारा स्थगन आवेदन का निपटारा करने से पहले उचित रूप से स्थापित अपील में स्थगन आवेदन दायर किया जाता है;

(2). यहां तक कि जब अपील में स्थगन आवेदन का निपटारा किया जाता है, तो वसूली एक उचित अवधि के बाद ही शुरू की जाएगी ताकि निर्धारिती एक उच्च मंच का रुख कर सके।

(3). हालांकि, ऐसे मामलों में जहां निर्धारण अधिकारी के पास यह मानने का कारण है कि निर्धारिती मांग को विफल कर सकता है या यह राजस्व के हित में समीचीन है, जैसा कि धारा 78 के प्रावधान के तहत प्रदान किया गया है, एक वसूली हो सकती है, लेकिन निर्धारिती को नोटिस के साथ, जो नोटिस इसे शुरू करने के कारणों को दर्शाता है और उस कम समय को निर्दिष्ट करता है जिसके भीतर निर्धारिती को देय राशि की पूर्ति करने का निर्देश दिया जाता है;

(4). हालांकि एक बैंक खाते को संलग्न किया जा सकता है; राशि निकालने से पहले, निर्धारिती को उचित पूर्व सूचना दी जानी चाहिए ताकि निर्धारिती प्रतिनिधित्व कर सके या कानून में किसी उपाय का सहारा ले सके;

(5). हम कर प्राधिकारियों को पुनः स्मरण कराते हैं, जैसा कि **यू.टी.आई. म्यूच्यूअल निधि** (उपर्युक्त) मामले में किया गया था, कि कर अधिनियम के अंतर्गत कार्यरत प्राधिकारी मात्र कर-संग्रहकर्ता की तरह कार्य न करें, बल्कि एक अर्ध-न्यायिक प्राधिकारी) के रूप में कार्य करें, जिन पर राजस्व के हितों की रक्षा करने का सार्वजनिक दायित्व निहित है और साथ ही साथ करदाता को होने वाली कठिनाइयों को कम करने की आवश्यकता के बीच संतुलन बनाए रखना है'(एस. आई. सी.-यू. टी. आई. म्यूचुअल फंड)।

17. हम यह पाए बिना नहीं रह सकते कि कर प्राधिकरण द्वारा, विशेषकर उस अधिकारी द्वारा जिसने परिशिष्ट-3 आदेश जारी किया, एक निश्चित अतिक्रमण किया गया है। अधिकारी ने मूल्यांकन आदेश के अनुसार देय राशि की वसूली गुपचुप तरीके से करदाता के बैंक खातों से कर ली, जबकि करदाता को न तो उचित सूचना दी गई और न ही माँग की पूर्ति के लिए कोई समय निर्दिष्ट किया गया। भले ही यह कार्रवाई तात्कालिकता अथवा राजस्व के हित में प्रेरित बताई गई हो, किन्तु प्रस्तुत मामले में दर्ज कारणों से ऐसा उद्देश्य स्पष्टतः परिलक्षित नहीं होता। दोहराव के जोखिम के बावजूद,अधिकारी द्वारा बताए गए कारणों को फाइलों के तह में छिपा कर रखा गया था; वे भी विश्वसनीय नहीं थे। कर निर्धारण वर्ष का अंत और एक या दो दिन की बैंक छुट्टियां, हमें विश्वास नहीं है कि ये किसी चालू व्यवसाय के खाते में रखी गई राशि को जब्त करने के लिए पर्याप्त कारण हैं। यदि उक्त राशि वसूल नहीं की जाती, तो राज्य और उसके राजस्व नहीं डूबते, लेकिन किसी व्यवसाय के बंद होने की पूरी संभावना होती है, बिना तरल निधि के, विशेष रूप से एक चालू व्यवसाय के, जिस पर अपने कर्मचारियों, अन्य लेनदारों आदि के प्रति देनदारियां हों।

18. कराधान कानून के तहत कर अधिकारियों की कार्रवाइयों को अच्छी अंतरात्मा और विवेकपूर्ण तर्क के साथ शांत किया जाना चाहिए, जो तत्काल मामले में कानून के शासन के स्थापित सिद्धांतों का पूरी तरह से अपमान था; सर्वोच्च शासन तब भी जब व्यापक भलाई और कल्याण के लिए धन का अनिवार्य निष्कर्षण होता है, जो हमेशा कर का उद्ग्रहण होता है। कर प्राधिकरण को व्यापार और अर्थव्यवस्था के एक सहायक के रूप में भी कार्य करना चाहिए, न कि केवल एक जबरन वसूली करने वाले के रूप में, जो हमेशा अपने व्यक्तिगत एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए अपने पदानुक्रमित वरिष्ठों को संतुष्ट करने की कोशिश करता है। हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि जिस कार्रवाई की शिकायत की गई थी, वह हठधर्मी और मनमाना थी।

19. जैसा कि हमने अवलोकन किया, अधिनियम की योजना में निर्धारण प्राधिकरण पूरी राशि की वसूली नहीं कर सकता था। धारा 112, अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष द्वितीय अपील के लिए, प्रथम अपीलीय चरण में भुगतान की गई दस प्रतिशत राशि के अतिरिक्त, देय कर राशि का बीस प्रतिशत प्रदान करती है। धारा 112(8) के तहत ऐसा भुगतान किए जाने पर, यह भी आवश्यक है कि आगे की वसूली कार्यवाही स्थगित कर दी जाए। इसलिए, जब कर निर्धारण अधिकारी ने धारा 78 के प्रावधान के तहत कार्य किया था, तब भी अपीलीय प्राधिकरण का गठन नहीं किया गया था, तो जो वसूला जा सकता था वह प्रथम अपील दायर करने के लिए भुगतान की गई राशि के अतिरिक्त देय कर राशि का केवल बीस प्रतिशत था। अनुलग्नक-3 के आदेश से हम देखते हैं कि बी.जी.एस.टी. और सी.जी.एस.टी. अधिनियम दोनों के तहत, देय कर राशि 18,91,609.00 रुपये है और मांग 2,00,000 रुपये की की गई है। सी.जी.एस.टी. और बी.जी.एस.टी. अधिनियम के तहत 34,94,161.00 रुपये प्रत्येक की राशि ब्याज और जुर्माने सहित है। हमने यह भी देखा है कि अनुलग्नक-2 आदेश के तहत उठाई गई कुल मांग से 1,89,161.00 रुपये कम कर दिए गए हैं, जो संभवतः करदाता द्वारा प्रथम अपीलीय चरण में किए गए दस प्रतिशत भुगतान का हिस्सा है।

20. अतः, अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील करने के लिए, करदाता द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि 7,56,644.00 रुपये थी, जो कि बी.जी.एस.टी. और सी.जी.एस.टी. अधिनियम के तहत देय कर का बीस प्रतिशत है। अतः, जब्त की गई कुल राशि 69,88,322.00 रुपये में से शेष राशि आज से दो सप्ताह के भीतर करदाता को चुका दी जाएगी, अन्यथा 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज लगेगा। यदि उपरोक्त निर्देशानुसार, राशि दो सप्ताह के भीतर चुका दी जाती है, तो यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि अंततः करदाता के विरुद्ध मांग की पुष्टि

हो जाती है, तो अनुलग्नक-3 के आदेश के अनुसार बैंकों द्वारा राशि जमा करने की तिथि और उपरोक्त निर्देशानुसार वापसी की तिथि के बीच, इस कानून के तहत कोई ब्याज का दावा नहीं किया जाएगा; चूँकि राज्य को अपने खजाने में जमा राशि का लाभ मिला था। यदि देयता अलग कर दी जाती है, तो जिन अवधियों के लिए करदाता को वसूली गई राशि से वंचित रखा गया था, वह विभाग से ब्याज का दावा करने की हकदार होगी।

21. हमारा यह भी मत है कि जिस अधिकारी ने अनुलग्नक-3 आदेश जारी किया, जिसने वैधानिक प्रावधानों और कानून के स्थापित सिद्धांतों का पूर्णतः उल्लंघन करते हुए कार्य किया, उसे करदाता को लागत के रूप में 5,000/- (पाँच हज़ार) रुपये का भुगतान करना चाहिए; जिसकी रसीद तत्काल रिट याचिका में दो सप्ताह के भीतर दाखिल की जानी चाहिए।

22. रिट याचिका की अनुमति हमारे द्वारा ऊपर दिए गए निर्देश और दिशानिर्देश के साथ दी गई है।

(के. विनोद चंद्रन, मुख्य न्यायाधीश)

(पार्थ सारथी, न्यायमूर्ति)

पी.के.पी./-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।